IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
Volume 2, Issue 1, November 2022
Impact Factor: 6.252

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की चुनौतियों और अवसरों पर एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

An Analytical Study on Challenges and Opportunities of NEP 2020

Dr. Aslam Sayeed[1] and Pratima Shukla[2]
Professor, Department of Commerce[1]
Research Scholar[2]
Amicable Knowledge Solution University, Satna, Madhya Pradesh, India[1]
Awadhesh Pratap Singh University, Rewa, Madhya Pradesh, India[2]
proff.aslam@gmail.com

सारॉंशः

शिक्षा से आर्थिक और सामाजिक प्रगति होती है इसलिए प्रत्येक देश अपनी परंपरा के अनुसार अलग–अलग शिक्षा प्रणाली अपनाते हैं क्योंकि किसी भी देश के विकास के लिए स्कूल और कॉलेज स्तर पर एक अच्छी तरह से सोची समझी और परिभाषित की गयी भविष्य की शिक्षा नीति की आवश्यकता होती है,

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020), जिसे 29 जुलाई 2020 को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था, ये भारत की नई शिक्षा प्रणाली के दृष्टिकोण को रेखांकित करता है पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 पर नई शिक्षा नीति 2020 एक सुधार है । यह नीति व्यापक है इसमें प्रारंभिक शिक्षा के लिए जो रुपरेखा बनाई गयी है उसमे उच्च शिक्षा के साथ–साथ भारत के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रो में व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए भी स्थान दिया गया है

जैसा कि ऊपर ये बताया गया की NEP 2020, 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर किया गया एक सुधार है जिसके लिए जनवरी 2015 में, पूर्व कैबिनेट सचिव टी.एस.आर. सुब्रमण्यम के नेतृत्व में एक समिति गठित की गयी जिसने नई शिक्षा नीति के लिए परामर्श प्रक्रिया शुरु किया इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर जून 2017 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के पूर्व प्रमुख कृष्णास्वामी कस्तूरीरंगन के नेतृत्व में एक पैनल द्वारा 2019 में एनईपी का मसौदा प्रस्तुत किया गया था नई शिक्षा नीति के इस मसौदे को लेकर पूरे देश में विभिन्न स्तरों पर कई सार्वजनिक परामर्श किये बाद में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा एक कठोर परामर्श प्रक्रिया के निष्कर्ष के आधार पर नई शिक्षा नीति को जारी किया गया.

नीति का उद्देश्य यह है की 2021 तक भारत की शिक्षा प्रणाली को बदलने के लिए भरसक प्रयास किया जाये साथ ही नीति जारी होने के फौरन बाद सरकार ने स्पष्ट किया कि किसी को भी किसी भाषा विशेष का अध्ययन करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा साथ में ये भी कहा गया कि शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी से किसी क्षेत्रीय भाषा में परिवर्तित नहीं किया जाएगा।

एनईपी में भाषा नीति की प्रकृति में व्यापक दिशानिर्देश दिए गए और यह कहा गया की यह राज्यों, संस्थानों और स्कूलों पर निर्भर करता है कि वे इस नयी शिक्षा नीति के कार्यान्वयन पर स्वविवेक से निर्णय लें क्योकि भारत में शिक्षा एक समवर्ती सूची का विषय है।

भारत में कर्नाटक मध्यप्रदेश और हिमाचल प्रदेश में नई शिक्षा नीति 2020 लागू कर दिया गया है। ऐसी आशा की जा रही है नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 तक भारत के सभी स्कूलों में लागू कर दी जाएगी

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
Volume 2, Issue 1, November 2022
Impact Factor: 6.252

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020
   https://www.mhrd.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/nep/ NEP_Final_English.pdf
2. मसौदा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019,
   https://innovate.mygov.in/wpcontent/uploads/2019/06/mygov15596510111.pdf
3. योजना पत्रिका
4. अन्य पेपर लेख